अहिल्यानगर, महाराष्ट्र

डिजिटल नवाचार के माध्यम से ई-गवर्नेंस में तेजी

संपादित : **सुषमा मिश्रा**

अहिल्यानगर डिजिटल शासन और आईसीटी-संचालित विकास में महाराष्ट्र के अग्रणी जिलों में से एक के रूप में उभरा है। पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित सेवाएँ लाने के दृष्टिकोण से, जिले ने वास्तविक समय जल प्रबंधन प्रणालियों से लेकर घर-घर सरकारी सेवाओं की डिलीवरी तक, तकनीकी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपनाया है।

एआई-संचालित उपस्थिति प्रणालियों, ओपन डेटा प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और जीआईएस-आधारित निगरानी उपकरणों को एकीकृत करके, अहिल्यानगर इस बात में नए मानक स्थापित कर रहा है कि कैसे तकनीक ज़मीनी स्तर पर शासन को मज़बूत कर सकती है।

ऐतिहासिक रूप से,इस ज़िले का इतिहास 1494 ईस्वी से जुड़ा है, जब मलिक अहमद ने अहमदनगर को निज़ामशाही वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। सदियों से, इसकी सीमाएँ विकसित होती रहीं, और अक्टूबर 2024 में, महारानी अहिल्याबाई होल्कर के सम्मान में ज़िले का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर रखा गया।

जिले में आईसीटी पहल

अहिल्यानगर जिला वेबसाइट

ahilyanagar.maharashtra.gov.in

आधिकारिक अहिल्यानगर जिला वेबसाइट, जो एस3वास फ्रेमवर्क पर निर्मित है, एक बहुभाषी, मोबाइल-अनुकूल पोर्टल है जो सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप गेटवे के रूप में कार्य करता है।

यह बताता है:

- **इतिहास और विरासत:** जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रदर्शन।
- **जनसांख्यिकी और शासन:** जनसंख्या, प्रशासनिक व्यवस्था और संसाधनों की विस्तृत जानकारी।

पवन रामलाल टेम्भुर्ने
वैज्ञानिक/ तकनीकी सहायक - ए व डीआईओ
pr.tembhurne@nic.in

अहिल्यानगर डिजिटल शासन में अग्रणी बनकर उभरा है, जहाँ सेवाओं को तेज़, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जलदूत की रीयल-टाइम वाटर टैंकर ट्रैकिंग, सेवादूत द्वारा प्रमाणपत्रों की घर-घर डिलीवरी, चेहरे से पहचान के साथ ए.ई.बी.ए.एस., सड़क सुरक्षा के लिए आई.आर.ए.डी. और ओपन डेटा प्लेटफ़ॉर्म जैसी पहल नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति जिले की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवाचार को जवाबदेही के साथ जोड़कर, जिला यह प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) दैनिक शासन को बदल सकती है।

- **निविदाएँ और भर्ती:** अनुबंधों और रोज़गार के अवसरों पर पारदर्शी अपडेट।
- **नागरिक सेवाएँ:** प्रमाणपत्रों, कल्याणकारी योजनाओं, शिकायत निवारण और आवेदन ट्रैकिंग तक आसान पहुँच।
- **पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था:** पर्यटन स्थलों, त्योहारों और निवेश के अवसरों की जानकारी।

जी.आई.जी.डब्ल्यू. सुगम्यता मानकों के अनुरूप, यह पोर्टल समावेशिता, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस सुनिश्चित करता है।

जलदूत

jaldoot.ahmednagar.gov.in

जलदूत पोर्टल, अहिल्यानगर की प्रमुख डिजिटल पहल है जो वास्तविक समय में टैंकर प्रबंधन के माध्यम से जल संकट से निपटने के लिए है। यह तकनीक और शासन को एक साथ जोड़कर यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी समुदायों तक पानी कुशल, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से पहुँचे।

मुख्य विशेषताएँ:

- **डिजिटल अनुरोध प्रणाली:** ग्राम सेवक (गाँव) और उप-अभियंता (शहरी क्षेत्र) टैंकर अनुरोध ऑनलाइन जमा करते हैं।

एनआईसी आईसीटी गतिविधियों में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। इसने आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने और राज्य एवं केंद्र दोनों ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे अहिल्यानगर में आयोजित कैबिनेट बैठक के लिए आईटी सहायता प्रदान करना। ई-ऑफिस, एआई-संचालित नवाचारों जैसे भाषिणी, चेहरा पहचान सक्षम जिला प्रशासन के साथ ए.ई.बी.ए.एस. और कई अन्य आईसीटी कार्यान्वयन में इसका योगदान इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। मैं एनआईसी अहिल्यानगर को बधाई देता हूँ और सफलता की कामना करता हूँ। मैं भविष्य में और भी कई ई-गवर्नेंस पहलों की आशा करता हूँ।

डॉ. पंकज आशिया, आईएएस
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अहिल्यानगर

- **स्वचालित ऑर्डर जनरेशन:** अनुरोधों को स्वीकृत किया जाता है और टैंकर ऑर्डर तुरंत जनरेट किए जाते हैं।
- **रीयल-टाइम ट्रैकिंग:** टैंकर जीपीएस-सक्षम होते हैं, और अधिकारियों द्वारा एक मोबाइल ऐप के माध्यम से उनकी आवाजाही की निगरानी की जाती है।
- **कुशल प्रेषण:** खंड विकास अधिकारी शेड्यूलिंग और वितरण का समन्वय करते हैं।
- **नागरिक पहुँच:** निवासी टैंकरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और समर्पित जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से डिलीवरी को

ट्रैक कर सकते हैं।

अनुमोदन कार्यप्रवाह, जीपीएस ट्रैकिंग और नागरिक भागीदारी को एकीकृत करके, जलदूत ने जिले में जल संकट के प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल ढांचा तैयार किया है।

जी.एम. सेवादूत

gmsevadoot.ahmednagar.gov.in

जी.एम. सेवादूत एक ई-गवर्नेंस पहल है जो प्रशिक्षित ग्राम-स्तरीय एजेंटों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों के दरवाजे तक पहुँचाती है। यह प्लेटफ़ॉर्म सरकारी कार्यालयों में प्रत्यक्ष रूप से जाने की आवश्यकता को कम करता है, जिससे सुविधा, दक्षता और आवश्यक सेवाओं तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित होती है।।

यह कैसे काम करता है:

- **ऑनलाइन अपॉइंटमेंट:** नागरिक पोर्टल के माध्यम से निवास या आय प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ बुक कर सकते हैं।
- **जीएम सहायता:** एक ग्राम मंत्री या ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) नागरिक के घर जाकर दस्तावेज़ एकत्र करता है।
- **डिजिटल प्रसंस्करण:** आवेदनों का प्रसंस्करण संबंधित सरकारी पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
- **होम डिलीवरी:** अंतिम डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आवेदक के निवास पर डाक द्वारा भेजे जाते हैं।

प्रौद्योगिकी को अंतिम-मील सेवा वितरण के साथ जोड़कर, जीएम सेवादूत यह सुनिश्चित करता है कि शासन समावेशी, नागरिक-केंद्रित और वास्तव में सुलभ हो।

मुख्यमंत्री के 150 दिवसीय कार्यक्रम की पहल

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ज़िले ने प्रमुख ई-गवर्नेंस उपकरण लॉन्च किए, जिनमें शामिल हैं:

- **ज़िला वेबसाइट अपडेट:** अधिक पारदर्शिता के लिए आरटीआई एकीकरण के साथ उन्नत।
- **व्हाट्सएप चैटबॉट:** सरकारी सेवाओं तक त्वरित और उपयोगकर्ता-अनुकूल पहुँच प्रदान करना।
- **लुकर स्टूडियो डैशबोर्ड:** कलेक्टर को वास्तविक समय में ज़िले की गतिविधियों की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करना।

▲ चित्र 3.2 : एनआईसी अहिल्यानगर ने 6 मई 2025 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल बैठक में तकनीकी सहयोग दिया, जिसमें अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती और विरासत संरक्षण पर केंद्रित विकास योजनाएँ रेखांकित की गईं

ओपन डेटा पहल

data.gov.in पर एक मुख्य डेटा अधिकारी (सीडीओ) खाता बनाया गया है, जिससे जिला डेटासेट को खुले, मशीन-पठनीय प्रारूपों में प्रकाशित कर सकेगा। इससे पारदर्शिता, नवाचार और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख कार्यक्रम

जामखेड में कैबिनेट बैठक

महारानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में, महायुति मंत्रिमंडल ने 06 मई 2025 को उनके जन्मस्थान चोंडी, जामखेड में एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में एक दूरदर्शी शासक के रूप में उनकी विरासत को रेखांकित किया गया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने में जिले की भूमिका पर ज़ोर दिया गया। इस बैठक के एजेंडे में एक व्यापक विकास पैकेज पर चर्चा शामिल थी, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार और संरक्षण।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विस्तार।
- अहिल्याबाई के समावेशी शासन मॉडल को प्रतिबिंबित करने के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ बनाना।

▼ चित्र 3.1 : आई.आर.ए.डी. परियोजना के तहत, एनआईसी जिला केंद्र ने 32 पुलिस थानों, दो आरटीओ तथा अन्य कार्यालयों में 1,472+ कर्मचारियों को 131+ प्रशिक्षण प्रदान किए

मुख्यमंत्री का विशेष कार्यक्रम

6 मई 2025 को, महायुति मंत्रिमंडल ने महारानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में अपनी बैठक आयोजित की। इस बैठक के एजेंडे में एक व्यापक जिला विकास पैकेज को मंजूरी देना शामिल था, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं और ऐतिहासिक स्मारकों का नवीनीकरण शामिल था।

एईबीएएस प्रशिक्षण

1 अगस्त 2025 को, जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए उपस्थिति ट्रैकिंग को आधुनिक बनाने हेतु चेहरे से प्रमाणीकरण के साथ आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की। प्रशिक्षण सत्र सुचारू रूप से अपनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रॉक्सी उपस्थिति को न्यूनतम करने के लिए आयोजित किए गए।

मानव संपदा

कलेक्टर कार्यालय ने डिजिटल अवकाश प्रबंधन के लिए मानव संपदा लागू की है, जिससे कुशल ट्रैकिंग, अनुमोदन और रिकॉर्ड-कीपिंग संभव हो पाई है। यह जिले में कागज रहित प्रशासन और बेहतर मानव संसाधन दक्षता की दिशा में एक और कदम है।

अग्रिम दिशा

भविष्य की ओर देखते हुए, अहिल्यानगर का लक्ष्य नागरिक-केंद्रित सेवाओं का विस्तार करना, डेटा-साझाकरण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना और स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों का अन्वेषण करना है। अधिकारियों की सतत क्षमता-वृद्धि के साथ-साथ बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से डिजिटल विभाजन को मिटाने के प्रयास भी प्रमुख रहेंगे। इन पहलों को आगे बढ़ाकर, ज़िला भारत में ई-गवर्नेंस के लिए एक डिजिटल रूप से सशक्त मॉडल के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी अहिल्यानगर जिला केंद्र
पाँचवीं मंजिल, बी विंग, जिला कलेक्टर कार्यालय
सवेदी, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र - 414003
ईमेल: dio-ahn@nic.in, फोन: 0241 - 2343328